







# विचार

स्वास्थ्य बीमा से वंचित 82 प्रतिशत दिव्यांगों को  
‘आयुष्मान भारत’ के साथ जोड़ने की जरूरत

भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना को चलाने वाली नैशनल हैल्थ अथॉरिटी की बैबसाइट पर देश में 76,54,49,221 आयुष्मान हैल्थ कार्ड बनाने का दावा किया गया है। इनमें से 52,08,653 लोगों का हैल्थ डाटा भी इन कार्ड्स के साथ लिंक करने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इस योजना से करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी योजना देश में लागू होने के बावजूद एक ऐसा वर्ग इस योजना का फायदा लेने से चूक रहा है जो शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है। ‘राष्ट्रीय दिव्यांगता नैटवर्क’ द्वारा हाल ही में पेश की गई ‘नैशनल सेंटर फार प्रमोशन आँफ एम्प्लायमेंट फार डिसेबल्ड पीपुल’ (एन.सी.पी.ई.डी.पी.) की एक सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 82 प्रतिशत दिव्यांगों के पास किसी प्रकार का कोई सेहत बीमा नहीं है और 42 प्रतिशत दिव्यांगों को सरकार की आयुष्मान भारत योजना की जानकारी ही नहीं है। इस सर्वे में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5,000 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों की राय ली गई है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 28 प्रतिशत दिव्यांगों ने ही आयुष्मान भारत की योजना का लाभ लेने की कोशिश की। एन.सी.पी.ई.डी.पी. के कार्यकारी निदेशक ‘अरमान अली’ ने कहा कि सर्वे की संख्या महज आंकड़े नहीं हैं बल्कि उन लोगों की हालत दर्शाती है जो आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल से वर्चित रह गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बीमा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेषाधिकार ही नहीं, यह जीवन-यापन के लिए एक आवश्यकता है और दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में दिव्यांगों के इस अधिकार की रक्षा करने वाला फैसला भी सुनाया था। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ‘प्रतिभा सिंह’ ने ‘सौरभ शुक्ला’ बनाम ‘मैक्स बूपा हैल्थ लाइफ इंश्योरेंस’ और अन्य के मध्य चले एक मामले की सुनवाई के दौरान 13 दिसम्बर, 2022 को सुनाए गए अपने फैसले में कहा था कि जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल होता है। अदालत ने अपने फैसले के दौरान ‘इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इण्डिया’ (आई.आर.डी.ए.) को आदेश दिया था कि वह सभी इंश्योरेंस कम्पनियों की एक बैठक करके उन्हें दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं जारी करने का आदेश दे लेकिन अदालत के इस फैसले के बावजूद 3 साल तक इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ है। दिव्यांगों के बीच अपने स्वास्थ्य अधिकारों को लेकर जागरूकता की कमी का भी बीमा कम्पनियां फायदा उठा रही हैं और उन्हें हैल्थ इंश्योरेंस जैसे स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार से वर्चित रखा जा रहा है। ‘अरमान अली’ ने सरकार के मानदंडों पर भी सवाल उठाया और कहा कि आयुष्मान भारत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करता है, लेकिन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऐसा कोई पावधान नहीं है।

मोदी राज में किसान की यही नियति बन गई है। एक मुसीबत से जान छूटी तो दूसरी तैयार। ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने तीन किसान विरोधी कानूनों को हराया। इधर किसान एम.एस.पी. हासिल करने के लिए लंबे संघर्ष की तैयारी में जुटे लेकिन उधर सरकार इन्हीं कानूनों को पिछले दरवाजे से लाने के लिए नैशनल फेमवर्क ऑन एपीकल्चर मार्केटिंग का मसौदा लेकर खड़ी हो गई। किसान संगठनों के पुरजोर विरोध के चलते इस मोर्चे पर ब्रेक लगी। इतने में नई मुसीबत आन खड़ी हुई। अब भारत सरकार अमरीका के साथ एक बड़ा व्यापार समझौता करने जा रही है। इसकी गाज भारत के किसान पर पड़ेगी। अगर आने वाले कुछ महीनों में देश के किसान एकजुट होकर प्रतिरोध नहीं करते, तो किसान के भविष्य पर एक बार फिर संकट मंडरा सकता है।

जनरात मुद्रा सकारा हा।  
25 से 29 मार्च तक ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व में अमरीका के वाणिज्य विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया। एजेंडा था अमरीका और भारत के बीच एक द्विपक्षीय समझौते की रूपरेखा तैयार करना। भारत आकर लिंच ने अपने राष्ट्रपति ट्रम्प की तर्ज पर भारत के ही प्रधानमंत्री को आंखें दिखाई। भारत सरकार ने चूं नहीं की। चार दिन की बातचीत को गुप रखा गया। आखिर में एक चिकना-चुपड़ा बयान जारी हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जानकार बता रहे हैं कि भारत सरकार ने अमरीका जनरात के जापात पर लगाता है, अमरीका भी उस शुल्क लगाएगा। यही नहं अमरीका की विदेश नीति से होगा, उस पर विशेष शु जाएगा। जब प्रधानमंत्री मो गए तो उनके सामने ट्रम्प ने कहा कि भारत अमरीकी म ज्यादा शुल्क लगाता है और उठीकरण करवाएगा। प्रधानमंत्री ने समय की मोहलत मांगी। व कुछ महीने के भीतर ही अमरीका व्यापक समझौता करेंगे। अमरीका ने 2 अप्रैल की जव

**‘दोपहिया वाहन के साथ देने पड़ेंगे दो हैल्मेट’  
‘लेकिन सती से इसे लागू करना होगा’**

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री 'नितिन गडकरी' देश के उन चंद नेताओं में से एक हैं जो न सिर्फ स्वच्छ राजनीति के पैरोकार हैं बल्कि अपने विभाग के काम को भी संजीदगी से लेते हैं। देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कार चालकों की जान बचाने के लिए 2023 में उन्होंने स्वदेशी कार ट्रैश टैस्ट प्रोग्राम 'भारत न्यू कार असैसमेंट प्रोग्राम' (भारत एन कैप) लांच किया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत अब अमरीका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद इस तरह का 'कार ट्रैश टैस्ट प्रोग्राम' लागू करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन चुका है। इसके अंतर्गत कार निर्माताओं को कार की मजबूती की जांच करने के लिए कार का 'ट्रैश टैस्ट' करवाना अनिवार्य है। कारों के 'ट्रैश टैस्ट' के बाद 'भारतीय वाहन निरीक्षण और प्रमाणन एजेंसी' (ए.आई.ए.सी.टी.) तथा भारत सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कार की मजबूती के आधार पर उसे 'सिंगल स्टार' से 'फाइव स्टार' तक की रैंकिंग देते हैं।



इस रैकिंग से ग्राहकों को कार खरीदते समय उसकी मजबूती की पूरी जानकारी हासिल होती है। इस प्रोग्राम से पूरे भारत में कार चालकों की सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मौतों और घायलों की संख्या कम होने की उम्मीद है। अब 'नितिन गडकरी' ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहन के साथ खरीदार को अनिवार्य रूप से 'आई.एस.आई. मार्क' वाले दो हैल्मेट देने की नीति की घोषणा की है। दिल्ली में आयोजित एक 'ऑटो सम्पिट' में उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 'टू व्हीलर हैल्मेट मैन्युफेक्चरर्स एसोसिएशन' (टी.एच.एम.ए.) के अध्यक्ष 'राजीव कपूर' ने 'नितिन गडकरी' की इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि यह नियम मौजूदा समय में देश की आवश्यकता है। उन्होंने 'नितिन गडकरी' की इस पहल को सड़क सुरक्षा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह कदम भारत में सुरक्षित और समझदारी भरा दोपहिया यात्रा के नए युग की शुरुआत करेगा। 'श्री राजीव कपूर' ने कहा कि वाहन चालक और सहयात्री यदि हैल्मेट पहन कर यात्रा करेंगे तो इससे उनमें सुरक्षा के साथ-साथ जिम्मेदारी का भाव भी आएगा। हैल्मेट निर्माताओं द्वारा देश भर में ऐसे उच्च सुरक्षा मानकों वाले हैल्मेट की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हैल्मेट न पहनने के अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना भी सड़क दुर्घटनाओं के एक बड़े कारण के रूप में सामने आ रहा है।

हालांकि, इस तरह की लापरवाही के लिए वाहन चालक के चालान काटने का कानूनी प्रावधान है लेकिन पुलिस कर्मियों की संख्या कम होने के कारण इस तरह की लापरवाही भी नहीं रुक रही। सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए इस तरह वे कानूनी अपराध पर भी सख्ती की जरूरत है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में भारत का दुनिया में पहला स्थान है। 2022 में भारत में कुल 4.61 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। इनमें से 50,000 से ज्यादा मौतें बिना हैल्मेट के दोपहिया वाहन चालकों की थीं जिनमें 18 से 45 वर्ष के बीच की उम्र वे 35,692 दोपहिया वाहन चालक और 14,337 सहयात्री शामिल थे। उसी वर्ष बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चला रहा कुल 1,01,891 चालक और उनके सहयात्री घायल भी हुए थे। घायल होने वालों में 63,584 चालक और 38,303 सहयात्री शामिल थे। इसी प्रकार 2023 में भी भारत में हुए कुल 4.80 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.72 लाख लोगों की मौत हुई। बिना हैल्मेट के दोपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने की नीति में पिछले दो महीनों में यह दूसरा बड़ा प्रयास है। जनवरी महीने में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना हैल्मेट के दोपहिया वाहन चालकों को पैट्रोल न देने की नीति लागू की थी। 'नितिन गडकरी' का यह प्रयास अपने आप में सराहनीय है लेकिन राष्ट्र स्तर पर इस उत्तर प्रदेश सरकार की तरह सख्ती से लागू करने की जरूरत है, ताकि बिना हैल्मेट के दोपहिया वाहन चालकों की हो वाली मौतों को रोकना सुनिश्चित किया जा सके।

## बुलडोजर न्याय-न्यायिक व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता

तापमान बढ़ने के साथ राजनीतिक भारत में भी गर्मी बढ़ रही है और इसका कारण अभूतपूर्व बुलडोजर राजनीति है। इस भारी भरकम मशीन ने गौच प्राप्त कर लिया है क्योंकि भाजपा ने बुलडोजर की शक्ति को न केवल एक निर्जीव मशीन की शक्ति के रूप में, अपितु एक राष्ट्रवादी राजनीति के विचार के रूप में प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक सुदृढ़, निर्णायक, अच्छे और प्रभावी शासन का अंग है और इस तरह उसने कानून के शासन को कानून द्वारा शासन में बदल दिया है। इस भारी भरकम बुलडोजर को राजनीतिक चर्चा में लाने का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बनाम बुलडोजर बाबा को जाता है और वर्ष 2017 से वहाँ सांप्रदायिक दंगाइयों और अपराधियों के विरुद्ध इसका उपयोग किया जा रहा है। अल्पसंख्यक समुदायों के घरों को तोड़ने में इसकी सफलता के चलते अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी इसका समर्थन होने लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर को क्रमशः बुलडोजर मामा और बुलडोजर ताऊ के रूप में जाना जाता है। उसके बाद दिल्ली, असम, गुजरात, उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र और पंजाब ने भी राज्य प्रतिकार के रूप में बुलडोजर मॉडल को अपना लिया है। इसका कारण क्या है? मुंबई और नागपुर में सांप्रदायिक झड़पों के बाद मुस्लिमों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को तोड़ा गया। पटियाला, लुधियाना, मोहल्ली में तस्कर मादक द्रव्यों को बेचकर घर बना रहे हैं। यही नहीं, विपक्ष शासित राज्यों में भी ध्रुवीकरण बढ़ गया है। कांग्रेस शासित हिमाचल के शिमला के संजोली में एक मस्जिद को गिराया गया और इसी तरह कर्नाटक के हुबली में दंगाइयों के घरों को तोड़ा गया।

वर्ष 2022-23 में बुलडोजर द्वारा 1,53,820 और वर्ष 2024 में 7,407 घर गिराए गए और इनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दिल्ली, गुजरात और असम का स्थान आता है। गिराए गए घरों में 37 प्रतिशत घर मुसलमानों के हैं या मुस्लिम क्षेत्रों के हैं। इस बुलडोजर राजनीति ने एक बड़ा विवाद भी पैदा किया। विपक्ष इसे संविधान का किया जा रहा है। यहां पर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का न केवल दमन किया जा रहा है, अपितु ऐसा करने के बाद उत्साह का वातावरण भी तैयार किया जा रहा है। ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं कि देश की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, बुलडोजर बनेगा हथौड़ा।

प्रश्न उत्तर है कि क्या यह राजनीतिक बाहुबल और दादागिरी का प्रदर्शन है या यह कानूनी है और दग्धाइयों के विरुद्ध एक प्रतिरोधक है। हमारी लौकतांत्रिक जागरूकता इतनी कमज़ोर बन गई है कि ऐसे उदाहरण मानदंड और सिद्धांत बनते जा रहे हैं और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का इस भारी भरकम मशीन द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है और यह एक राजनीतिक औजार बन रहा है जिसका उपयोग एक मजबूत नेता की छवि बनाने के लिए भी किया जा रहा है और इससे सामाजिक मतभेद भी बढ़ रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने एक उल्लेखनीय निर्णय देकर बुलडोजर कार्रवाई पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। न्यायालय ने कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया का उपयोग किए बिना कथित आपाराधिक गतिविधियों में संलिप होने के आधार पर किसी व्यक्ति की संपत्ति को गिराना असर्वेधानिक है और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों तथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को 15 दिन का नोटिस देना होगा और उसकी बात सुननी होगी। किंतु विभिन्न राज्यों की सरकारें न्यायालय के निर्णय को नजरअंदाज कर रही हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था के बारे में गंभीर चिंता पैदा होती है। इससे भी अधिक डिक्षितात्मकीय की बात यह है कि कार्यपालिका न्यायालय के निर्णयों का पालन करने में विफल रही है। इससे न केवल कानून का शासन कमज़ोर हो रहा है अपितु न्यायालय की अवमानना के लिए एक खतरनाक पूर्वोदाहरण स्थापित हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि न्याय के इस स्वरूप में न तो उचित प्रक्रिया के लिए सम्मान है और न ही समय। इस संस्थागत कदम से न केवल कानून के शासन को खतरा पैदा हो रहा है अपितु इसके अंतर्गत दमनकारी नीतियों को भी अपनाया जा रहा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है।

# ट्रूप के डर से होगी हमारे किसान की लिंचिंग?



से भारत को मुक्त नहीं किया। साथ में इस प्रतिनिधिमंडल को भेजकर भारत सरकार पर टबाह करनाया है।

पर दबाव बनाया ह। सवाल यह है कि ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व वाले इस प्रतिनिधिमंडल के दबाव के चलते क्या भारत के किसान के हितों की लिंचिंग होगी? कृषि मामलों के जानकर और 'रूरल वॉइस' के संपादक हरवीर सिंह ने यह आशंका जताई है। उन्होंने याद दिलाया है कि हमारी सरकारों ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों से

कृषि क्षेत्र को बाहर रखा है। साथ ही सरकार को आगाह किया है कि इस वार्ता में कृषि उत्पाद को शामिल करने से भारत के किसान को नक्सान पहुंच सकता है। अब ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों से खरीदना शुरू कर दिया है। इसलिए अमरीका को नए बाजार की तलाश है, उसकी नजर भारत पर है।

क इक्सान का युक्सान पहुच सकता ह। यह आशंका आधारहीन नहीं है। पिछले कई वर्षों से अमरीका की नजर भारत के कृषि उत्पाद बाजार पर रही है। कृषि विशेषज्ञ हरीश दामोदरन ने अमरीका के कृषि व्यापार का विश्लेषण कर बताया है कि पिछले कई साल से चीन ने अमरीकी कृषि उत्पाद की खरीद कम कर दी है और उसका नजर भारत पर ह।

अमरीका के कृषि मंत्रालय ने बाकायदा भारत के मांस उद्योग का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत में आने वाले दशक में चिकन फीड और पशुओं के लिए सोयाबीन और मक्का की मांग बढ़ेगी। यहां अमरीकी माल के खपत की अच्छी गुंजाइश है। अमरीका के

लिए दिक्कत यह है कि भारत ने भारी आयात शुल्क लगा रखा है। साथ ही अमरीका की जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के खतरे को देखते हुए इस पर पर भारत में पाबंदी है। अब ट्रम्प की दादागिरी के सहारे अमरीकी कृषि उत्पादक अपना माल भारत पर थोपने की कोशिश में हैं। कोशिश यह है कि अमरीका से होने वाले द्विपक्षीय समझौते में कुछ फसलों को भी शामिल कर लिया जाए। हर कोई जानता है कि ये फसलें कौन सी होंगी। सोयाबीन और मक्का के अलावा अमरीका की मुख्य दिलचस्पी कपास में होगी। साथ ही 'वॉशिंगटन सेब', अमरीकी नाशपाती और कैलिफोर्निया के बादम जैसे कुछ उत्पाद भी होंगे। फिलहाल अमरीका को गेहूं और दूध उत्पाद भारत में बेचने की कम गुजाइश दिखती है लेकिन भविष्य में यह भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इस आयात को वकालत सिर्फ अमरीका ही नहीं, भारत की कुछ कंपनियां भी कर रही हैं। पोल्ट्री उद्योग, मांस निर्यातकों और कपड़ा मिलों के मालिक भी चाहते हैं कि उन्हें सस्ते दाम पर माल मिले और उनका मुनाफा बढ़े। अगर इसका किसी को नुकसान है तो भारत के किसान को। पहले ही किसान अपनी फसल के वाजिब दाम से वंचित रहता है। ऐसे में अगर अमरीका जैसे बड़े देश के साथ कृषि व्यापार खुला गया तो भारत का किसान दोहरी मार झेलेगा। पिछले कुछ साल में मक्का उत्पादन अपने परंपरागत क्षेत्रों के बढ़कर बिहार और बंगाल तक पहुंचा है।





# क्या शिखर धवन को मिल गया दूसरा प्यार?

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं और एक बार फिर उन्हें प्यार हो गया है। धवन की लव अफेयर के चर्चा काफी समय से चल रहे हैं। उन्हें आईसीसी चैंपियंस टॉफी के दौरान एक मिस्ट्री गर्ल के साथ स्पॉट किया गया था उस दौरान से ही उनके अफेयर के चर्चे चल रहे हैं। वहीं इन दोनों को दुर्बई इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप मैच में भारत के बांगलादेश के खिलाफ मैच के साथ देखा गया था। इन दोनों की एक-साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं, जिसमें महिला को जब करीबी से जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये सोफी शाइन हैं। जो कि आयरलैंड की हैं। अब धवन ने अपने रिलेशन पर खुलकर बात कही है। दरअसल, धवन ने एक शो में कहा कि हाँ मैं लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं प्यार के मामले में बदकिस्मत था। बल्कि, मेरी पसंद कम अनुभव से आई थी। लेकिन अब मेरे पास अनुभव है और वह काम आएगा। ये मेरे लिए सीखने का एक मौका था। मैं हमेशा प्यार में रहता हूँ। वहीं जब धवन से पूछा गया कि क्या वह फिर से प्यार करने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने जबाब देते हुए कहा कि, मैं जानता हूँ कि क्रिकेट में बाउंसर से कैसे बचना है और मैं जानता हूँ कि अब आप मुझ पर बाउंसर फेंक रहे हैं।

## કગિસો રવાડા આઈપીએલ છોડ સાઉથ અફીકા લૌટે

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2025 में आरसीबी को हराकर अपनी दूसरी जीत का स्वाद चखने वाली गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज किंग्सो रबाडा महज 2 मैच खेलकर निजी कारणों से आईपीएल छोड़ स्वेदश लौट गए हैं। उनकी टीम गुजरात टाइटंस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली जीटी ने नहीं बताया है कि रबाडा कब तक लौटेंगे? गुजरात टीम ने एक बयान में कहा कि, किंग्सो रबाडा कुछ अहम निजी मसले से निपटने के लिए साउथ अफ्रीका लौट गए हैं। रबाडा ने पंजाब किंग्स और मुर्बई इंडियंस के खिलाफ एक एक विकेट लिया ता। उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलरू के खिलाफ

# सारा तेदुलकर ने ग्लोबल ई-फ्रिकेट प्रीमियर लीग में खरीदी मंबर्ड की टीम

नई दिल्ली (एजेंसी)। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर भी अब क्रिकेट में कूद गई हैं। दरअसल, सारा ने ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग में मुंबई फैंचाइजी खरीदी है। जीईपीएल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फैंस को इसके बारे में बताया। ई-क्रिकेट लीग की दुनिया में ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग सबसे बड़ी लीग में से एक है। पहले ही सीजन में ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले सीजन में 2 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन 2025 में कुल 910000 खिलाड़ियों के अपना नाम दर्ज करवाया है। जीईपीएल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि सारा तेंदुलकर ने ग्लोबल ई-क्रिकेट प्रीमियर लीग में मुंबई फैंचाइजी को खरीदा है। मुंबई की मालकिन बनने के बाद सारा तेंदुलकर ने कहा कि, क्रिकेट हमारे परिवार का अधिकार अंग रहा है। ई-स्पोर्ट्स में इसकी संभावनाओं को तलाशना रोमांचकारी है। जीईपीएलने में मुंबई फैंचाइजी की मालकिन होना एक सपना सच होने जैसा है।



**नई दिल्ली (एजेंसी)।** गुजरात टाइटंस ने बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली आरसीबी की टीम की ये आईपीएल 2025 में पहली हार है। टीम ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं। बैंगलुरु में खेले गए पहले

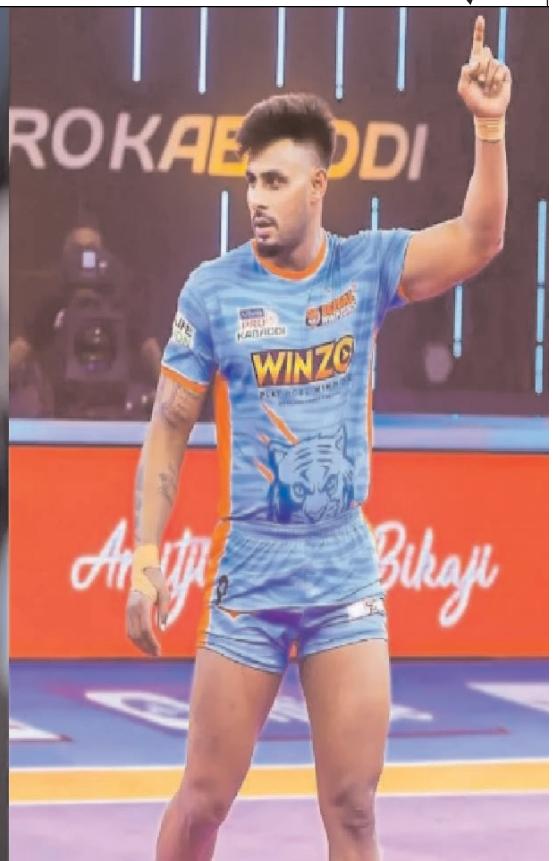
ये 3 खिलाड़ी हासिल कर सकते हैं पीकेएल में 1500 रुड पॉइंट्स

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** प्रो कबड्डी लीग में अभी तक मात्र दो ही रेडर ऐसे हुए हैं जिन्होंने 1500 रेड पॉइंट्स हासिल करने का कारनामा किया हुआ है। सबसे पहले परदीप नरवाल ने ये कारनामा किया था। परदीप नरवाल पीकेएल में 1800 से भी ज्यादा पॉइंट्स ले चुके हैं। उनके नाम प्रो कबड्डी लीग इतिहास में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स लेने का रिकॉर्ड है। इसके बाद मनिंदर सिंह का नंबर आता है। उन्होंने 1528 रेड पॉइंट्स अभी तक हासिल किए हैं। अब फैसं के मन में सवाल ये है कि इन दोनों के अलावा और कौन-

**प्रदर्शन कितना बढ़िया रहा है।** नवीन कुमार भी बहुत जल्द 1500 के आंकड़े को हासिल कर सकते हैं।

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अर्जुन देशवाल हैं जो अपने करियर में अभी तक 1174 रेड पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। अर्जुन देशवाल ने जयपुर पिंक पैंथर्स को पीकेएल का टाइटल जिताने में अहम योगदान दिया था। उनका प्रदर्शन पीकेएल में लगातार अच्छा रहा है। अर्जुन देशवाल जिस हिसाब से खेल रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वो पीकेएल में जल्द ही 1500 का आंकड़ा हासिल करलेंगे।

कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस आंकड़े को हासिल कर सकते हैं। प्रो कबड्डी लीग में युवा रेडर नवीन कुमार बहुत जल्द ही 1500 के आंकड़े को क्रॉस कर सकते हैं। नवीन कुमार ने अभी तक काफी जबरदस्त खेल दिखाया है। उन्होंने 107 मुकाबले अपने पीकेएल करियर में खेले हैं और इस दौरान 1102 रेड पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। इससे पता चलता है कि उनका



# दोनों हाथ से गेंदबाजी करने वाले अनोखे गेंदबाज का आईपीएल डेब्यू



नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल इतिहास में अब गजब टैलेंट आता रहा है। अब आईपीएल के 18वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद को एक अनोखा प्लेयर मिला है जो

दोनों हाथों से गेंदबाजी कर लेता है। अपनी इसी खूबी के कारण वह चर्चा में है। गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। जिसमें

कामिंदु मैंडिस ने अपना आईपीएल डेब्यू किया। दरअसल, वो पहले भी दोनों हाथों से बॉलिंग करने के कारण सुर्खियों में बने रहे हैं। अब आईपीएल यूनिवर्स को भी उन्होंने अपना टैलेंट दिखा दिया है। गजब की बात ये है कि उन्होंने एक ही मैच के एक ही ओवर में 2 अलग-अलग तरह से गेंदबाजी की है। श्रीलंका के कामिंदु मैंडिस ने कोलकाता के खिलाफ मैच में दाएँ और बाएँ हथ से भी गेंदबाजी की। ये बात है कि कोलकाता की पारी के 12वें ओवर की, जिसमें कामिंदु गेंदबाजी करने आए। कोलकाता के लिए क्रीज पर अंगकृष रघुवंशी और वेंकटेश अव्यर मौजूद थे। जब रघुवंशी खेल तब मैंडिस ने बाएँ गेंदबाजी की वर्ही जब ही गेंद पर बेंकटे स्ट्राइकिंग एंड पर प मैंडिस ने ना केवल बदला बल्कि दाएँ गेंदबाजी कर सबको दिया था। बता दें कि, साल जुलाई में भारत श्रीलंका के बीच खेली 20 सीरीज में मैंडिस ने गेंदबाजी व उस समय टीम इंडिया खिलाफ मैच में मैंडिस ने सूर्यकुमार यादव को बॉल से गेंदबाजी की थी व रिकू सिंह खेल रहे मैंडिस ने दाएँ हाथ से गेंदबाजी करनी शुरू की।

**जुलाई में इटली में खेली  
जाएगी होपमैन कप मिश्रित  
टीम टेनिस प्रतियोगिता**



# बार्सिलोना और रियाल मैड्रिड में होगा खिताबी मुकाबला



नई दिल्ली (एजेंसी)। बार्सिलोना  
ने बुधवार को यहां एटलेटिको मैड्रिड को  
सेमीफाइनल के दूसरे चरण में 1-0 से  
हराकर कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट के  
फाइनल में प्रवेश किया जहां उसका  
सामना अपने चिर प्रतिदंडी रियाल मैड्रिड  
से होगा। बार्सिलोना की तरफ से फेरान  
टोरेस ने पहले हाफ में गोल किया जो  
आखिर में निर्णायक साबित हुआ। इससे  
पहले इन दोनों टीमों के बीच फरवरी में  
खेला गया सेमीफाइनल का पहला चरण  
1-1 से बाकी रहा।

बार्सिलोना ने कुल मिलाकर 5-4 से जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई। यह पिछले चार सत्र में पहला अवसर है जबकि बार्सिलोना इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। रियाल मैड्रिड ने मंगलवार को अतिरिक्त समय तक चले और मैच में रियाल सोसिदाद को 5-4 के कुल स्कोर से पराजित करके फाइनल में जगह बनाई थी। इन दोनों टीमों के बीच 2013-14 सत्र के बाद पहली बार फाइनल खेला जाएगा। तब रियाल मैड्रिड ने विवाद जीता था।

# विराट कोहली की छोट को लेकर आरसीबी हेड कोच एंडी फ्लावर ने दिया बड़ा अपडेट,

# अयोध्या पहुंचकर मुंबई इंडियंस के खिलाडियों ने किए रामलला के दर्शन



कसान सूर्यकुमार ने आईपीएल 2025 के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस के लिए कसानी की थी। इस दौरान टीम को चेन्नई के खिलाफ हार झेलनी पड़ी।

